RAJYA SABHA

Thursday, the 20th November, 1986|29 Kartika, 1908 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Miyong Hydel Project in Sikkim

*241. SHRI LEONARD SOLOMAN SARING: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Sikkim propose to go ahead with the Miyong Hydel Project in North Sikkim, despite its non-clearance by the Department of Environment; and

(b) if so. what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) The Sikkim Government have been pressing for early approval of the project from environmental and forestry angles. The proposal, however, could not be assessed earlier because clarifications sought to consider diversion of forest land have been furnished only in October, 1986. While the Advisory Committee constituted under the Forest (Conservation) Act, 1980 has already considered the proposal on 11th November, 1986, it will be considered by the Environmental Appraisal Committee on 24th November, 1986.

श्री लेनार्ड सोलोमन सरिंग : सभापति महोदय, सिक्किम में बहुत सी नदियां मैगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। सिक्किम का दो तिहाई भाग जंगल है और उसके ऊपर हिमालय भी है। यह मियोंग हाइडल प्रोजेक्ट को गत साल ऊर्जा मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी थी। यह 7-8 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें देरी होने के कारण इस प्रोजेक्ट का खर्च डबल हो गया है। इस देरी के कारण जो इसकी कीमत बढ़ी है, इसके लिये कौन उत्तरदायी होगा ? ऐसे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को जल्द मंजूरी देने के लिये क्या मन्त्री जी एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम बनायेंगे और साथ ही साथ मंत्री जी हाउस को क्या यह आश्वासन देंगे कि इस प्रोजेक्ट को एक महीने के अन्दर स्वीकृति दे दी जायगी ?

श्री जैड० आर० अन्सारी : जनाबेवाला, जैसे मैंने अर्ज किया हैं स्टेट गर्वनमेंट से तथा प्रोजक्ट अथार्टीज से जो इन्फोरमेशन मांगी गई थीं, उसके देर में आने की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हुई है। अक्तूबर, 1986 में हमारे पास पूरी इनफोरमेशन आई और इसके आने के बाद ही फारेस्ट के दृष्टिकोण से उसका क्लीयरेंस हो गया है और 24 नवम्बर को एनवायर्जमेंट के दृष्टिकोण से इस प्रोजेक्ट की जांच होगी। जहां तक क्लीयरेंस का सवाल है अगर हमारे पास पूरी इनफारमेशन आ जायगी तो मैं यह एश्योरेंस देता हूं कि तीन महीने से ज्यादा हम किसी प्रोजेक्ट को क्लीयर करने में नहीं लगायेंगे, तीन महीने के अन्दर क्लीयर कर देंगे, बशर्ते कि सारी इनफारमेशन हमारे पास आ जाय। मजबूरी यह है कि हम जो इनफारमेशन चाहते हैं, वह सालों तक न आये तो हम किस बात पर फैसला करेंगे।

श्री लनार्ड सोलोमन सरिंग : मान्यवर, क्या मंत्री महोदय की जानकारी है कि सिक्किम गर्वनमेंट ने आपकी स्वीकृति के न आने के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट का टेण्डर सिक्किम हैराल्ड इनफारमेशन सर्विस जो गर्वनमेंट का है उसमें 17-18 अक्तूबर को दिया है, क्या आप उसकी जांच करेंगे और कार्यवाही करेंगे ?

श्री जैड० आर० अन्सारी : जनाबेवाला, जहां तक इस प्रोजेक्ट के इम्पलीमेंटेशन करने का सवाल है, अभी तक इस प्रोजेक्ट के इम्लीमेंटेशन के लिये कोई कार्यवाही सिक्किम गर्वनमेंट की तरफ से नहीं की गई है, हमने इस बात की जांच कर ली है। हम ने यह

इंस्ट्रक्शंस भी दे दी है कि जब तक एनवायर्नमेंट के दृष्टिकोण से इसका क्लीयरेंस न हो जाये उस वक्त तक कोई कार्यवाही प्रोजेक्ट पर नहीं की जाएगी।

SHRI LEONARD SOLOMAN SARING: Sir, I want your protection. Sir, the Sikkim Government have got the Information Service Herald. In that they have already put the tender. I can place it before the House if you require.

MR. CHAIRMAN: The Central Government has no information.

SHRI LEONARD SOLOMAN SARING: I have got the papers.

MR. CHAIRMAN: You may have. But the Central Government must have the information.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, सिक्किम गवर्नमेंट से हमने पता किया है, उनकी टेलीग्राम भी हमारे पास आ चुकी है कि हमने इस प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू नहीं किया है।

PROF. B. RAMACHANDRA RAO: Sir, the clearance of the schemes from the Department of Environment is very essential because of the fact that the environment in the area may be affected. My question is that once the clearance is given the Ministry of Environment and Forests should take care of the fact that the catchment areas is heavily afforested because it will take four or five years to prevent siltation.. Many of our hydel dams are silted to different degrees. The Periyar dam is, for instance, silted to the extent of one-third degree. Would they take care that once the clearance is given the Ministry of Environment and Forests sees that the catchment areas are heavily afforested to prevent further siltation.

SHRI Z. R. ANSARI: Sir, in the project itself when the clearance is given certain conditions are imposed on the project authorities that they should take care of afforestation and environment which is necessary for keeping the environment intact.

*242. [*The questioner (Shri Ramsinghbhai Pataliyabhai Rathvakali) was absent. For answer,* vide *cols.* 29—34 infra]

MR. CHAIRMAN: Next Question 243. Question No. 249 also relates to construction of nuclear power plants. So, both of them will be taken up together.

Construction of Nuclear Power Plants

@*243. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of nuclear power plants which have been cleared by Government have not been taken up for construction so far; and

(b) if so, what are the names of such Plants and what action is being taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) and (b) Government have taken a decision to locate two reactors of 235 MWe at Kaiga in Karnataka and two units of 235 MWe in Rajasthan. Preliminary work in respect of manufacture of long time cycle components for these 4 reactors is in progress. Development of infrastructure facilities at the two sites has also commenced.

@Starred Questions 243 and 249 were taken together.